

दैनिक

रोकथोक लेखनी

(R)

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मुस्लिमों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकलन करने महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की स्टडी



है. प्रस्ताव के अनुसार इस स्टडी में महाराष्ट्र के मुस्लिमों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर केन्द्रित होगा.

राज्य के 56 शहरों में होगी स्टडी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 56 शहरों में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षणिक स्थिति का आंकलन करने के लिए एक स्टडी शुरू की है. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है. बीते 21 सितंबर को जारी एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को इस स्टडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके लिए 33.92 लाख रुपये का निर्धारित किए गए हैं. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा यह स्टडी शुरू की गई

स्टडी राज्य के छह राजस्व संभागों के 56 शहरों में की जाएगी. इसमें मुस्लिम समुदाय की बहुलता वाले इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं के लाभों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा. टीआईएसएस द्वारा इन पहलुओं का स्टडी करके इलाके के विशिष्ट मुद्दों की पहचान की जाएगी. इस संबंध में सिफारिशें करने की संभावना है. सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि अगले चार महीने में इससे जुड़ी रिपोर्ट पेश की जाएगी.

मुंबई में टैक्सी और ऑटो से सफर करना होगा महंगा!



1 अक्टूबर से बढ़ेगा किराया ...!

मांग कर रहे थे।

यूनियन ने दी थी आंदोलन की चेतावनी

ठाणे : टैक्सी और रिक्शा से सफर करना अब महंगा हो सकता है। क्योंकि मुंबई सहित पुरे एमएमआर रीजन में ऑटो रिक्शा-टैक्सी का किराया एक अक्टूबर से बढ़ सकता है। रिक्शा के किराए में 2 रुपए और टैक्सी के किराए में 3 रुपए की बढ़ोतरी की जाने वाली है। इस प्रकार रिक्शा का किराया 21 रुपए से बढ़कर 23 रुपए और टैक्सी का किराया 25 से बढ़कर 28 रुपए होने वाला है। जबकि प्रति किलोमीटर के दार में भी वृद्धि की गई है। मंत्रालय में उद्योग मंत्री उदय सामंत की उपस्थिति में यूनियन पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस दौरान प्रभारी सचिव संजीव जायसवाल, एसटी महामण्डल के शेखर चन्ने, आरटीओ और ट्रैफिक विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों की मानें तो इस संबंध में जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुंबई में दो अगस्त की आधी रात से सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। साल 2022 में पांचवी दफा मुंबई में कंप्रेसड नेचुरल गैस (सीएनजी) और डोमेस्टिक पाइपड नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतों में इजाफा किये जाने और सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी के बाद से ऑटो-टैक्सी यूनियन ने भी किराए में बढ़ोतरी की

मुंबई सहित एमएमआर रीजन में ऑटो रिक्शा यूनियन ने खटुआ समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ईंधन की कीमतों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद टैक्सी किराए को संशोधित करने की आवश्यकता बताया था। साथ ही किराया बढ़ाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। ऑटो रिक्शा यूनियन का कहना था कि हमारी परिचालन लागत 1.31 रुपए प्रति किमी बढ़ गई है। फिलहाल एक रिक्शा का न्यूनतम किराया 21 रुपए है और पहले 1.5 किलोमीटर के बाद मौजूद किराया 14.20 रुपए प्रति किलोमीटर है।

नायर हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या, नहीं मिला सुसाइड नोट...



मुंबई : बृहन्मुंबई

महानगरपालिका के अंतर्गत चलने वाले नायर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक मेडिकल स्टूडेंट्स ने बुधवार को अपने घर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक, मृतक डॉ. श्रेयसा पाठकर मेडिकल कॉलेज की ऑब्ज्यूवेशनल थैरेपी विभाग की अंतिम वर्ष की मेडिकल स्टूडेंट्स थी। इसने अपने अग्रिपाड़ा इलाके के घर में गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है। आत्महत्या के समय घर में कोई नहीं था और इसके शव के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, जिस आत्महत्या की वजह की पहली उलझ गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि इस आत्महत्या के साथ बीते एक महीने में मुंबई के दो प्रमुख मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा सुसाइड करने का मामला अब तक सामने आ चुका है।

मुंबई में लगा पहला ST कष्टकरी जनसंघ यूनियन का बोर्ड



एस टी कष्टकरी जनसंघ का पदाधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस दौरान हजारों सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुये.

गलती से लगा ली फांसी, हुई मौत

विरार का 35 साल का शख्स पत्नी को डराने की कर रहा था कोशिश...

मुंबई : मुंबई से हैरान कर देने वाली खबर आ रही है. यहां एक 35 वर्षीय शख्स ने सोमवार रात अपने आवास पर झगड़े के दौरान अपनी पत्नी को डराने की कोशिश में गलती से फांसी लगा ली. पुलिस ने ये जानकारी दी है. विरार पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और घटना की जांच कर रही है. मृतक भगवान रामजी शर्मा अपनी 26 वर्षीय पत्नी चांदनीदेवी के साथ विरार पश्चिम में वीर सावरकर मार्ग स्थित लक्ष्मी निवास भवन में रहते थे. 500 रुपये नहीं लौटाने पर हुआ था झगडा दंपति ने छह दिन पहले ही बिल्डिंग में शिफ्ट किया था. मृतक



शर्मा भयंकर स्थित कपड़ा निर्माण इकाई में काम करते थे. पुलिस के मुताबिक भगवान ने अपनी पत्नी को कपड़े खरीदने के लिए 2,000 रुपये दिए थे. उसने 500 रुपये वापस करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया. इसी बात को लेकर दंपति में झगडा हो गया था. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हूउसने अपनी पत्नी के 500 रुपये नहीं लौटाने पर आत्महत्या करने की धमकी भी दी

थी, वह उसे डराने की कोशिश कर रहा था. उसने खुद को बेडरूम के अंदर बंद कर लिया और कहा कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है. हालांकि वह नाटक कर रहा था और उसने एक कपड़े का इस्तेमाल किया था लेकिन ये छत के पंखे में फंस गया. पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला किया दर्ज पुलिस के अनुसार, चांदनीदेवी ने तुरंत पड़ोसियों को खबर की थी जिसके बाद सभी फ्लैट में पहुंचे और बेडरूम का दरवाजा तोड़ा गया. सभी भगवान को पंखे से लटका पाकर सन्न रह गए. इसके बाद वे उसे नजदीकी अस्पताल ले गए लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया.

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

लौटता मानसून!

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इस मौसम में पहली बार लगातार बारिश का गवाह बना है। इससे एक ओर जहां खुशी है, वहीं जलभराव से जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है। बारिश कम या ज्यादा लगातार हो रही है और आने वाले दो दिनों तक इसी सिलसिले का अनुमान है। सड़क से लेकर हवाई यातायात तक असर पड़ा है,

कुछ सरकारी कार्यालयों में भी जलभराव से समस्या हो गई है। आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिन रास्तों पर जलभराव है, उनको छोड़कर अन्य रास्तों पर लोगों को चलने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। ध्यान रहे, ज्यादा बारिश की वजह से विगत दस दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश में दो बेहद दुखद दुर्घटनाएं हुई हैं। लखनऊ में दीवार गिरी थी, जिसमें नौ लोगों की मौत हुई, तो नोएडा में दीवार गिरने से चार की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में ही बारिश बीस से ज्यादा लोगों को काल के गाल में ले गई है।

जाते मानसून के समय की यह बारिश तनाव दे रही है, तो इसके लिए पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आमतौर पर मानसून 25 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी से विदा हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ देरी से जाएगा। मौसम विभाग ने सावधानी बरतते हुए येलो एलर्ट जारी कर रखा है। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम और नोएडा जैसे कमाऊ क्षेत्रों में जलभराव की शिकायत गंभीर है। अफसोस की बात है, हम बारिश को चंद दिनों की समस्या मानकर स्थायी समाधान से बच रहे हैं। शहरों को बारिश जनित समस्याओं से बचाने के लिए जितने प्रयास होने चाहिए, नहीं हो पा रहे हैं। बेशक, हमारे बड़े शहर अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा दबाव झेल रहे हैं, लेकिन लोगों को उनकी समस्याओं के साथ अपने हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान रहे, मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश के बीच आने वाले हफ्तों में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका है। लोगों को आसपास जलभराव न होने देने और शरीर ढकने वाले वस्त्र पहनने की सलाह दी गई है। ध्यान रहे, अकेले राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक डेंगू के 396 मामले सामने आए हैं। 17 सितंबर तक इस महीने में ही डेंगू के कुल 152 मामले दर्ज किए गए हैं। मतलब सावधानी समय की मांग है।

बारिश के कारण तात्कालिक चिंता बढ़ी है, लेकिन वास्तव में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य कुल मिलाकर बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में भले ही पिछले सप्ताह सामान्य से 192 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन पूरे मौसम में दिल्ली में 28 प्रतिशत कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो सामान्य से 31 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जबकि झारखंड में 20 प्रतिशत कम। अब हो रही बारिश सात्वना या राहत की तरह है, लेकिन पूरे मौसम में जो कमी रह गई है, उसे शायद दूर नहीं किया जा सकता। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण के राज्य बहुत खुशानसीब रहे हैं, जहां जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भी ठीकठाक बारिश हो चुकी है। ज्यादा चिंता पंजाब को लेकर है, हालांकि, उसे नहरों के जरिये कृषि के लिए पर्याप्त पानी मिल जाएगा। वैसे इस साल देश में धान उत्पादन में चार प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया है। बहरहाल, ज्यादा चिंता बेतरतीब बसते बड़े शहरों की है, जो चंद दिन बारिश से परेशान रहेंगे और आठ महीने जलाभाव का तनाव भी झेलेंगे।

✉ editor@rokhoklekhaninews.com

🐦 Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

BJP विधायक नितेश राणे ने देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी...

कहा- मुंबई से मराठी लोगों को भगाया जा रहा है

मुंबई : केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और कणकवली विधानसभा क्षेत्र के विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मराठी लोगों को न्याय दिलाने की मांग की है। अपने पत्र में नितेश राणे ने कहा है कि मुंबई में मराठी आबादी को शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने फडणवीस से इस समुदाय की समस्याओं पर गौर करने की अपील की है। नितेश ने उपमुख्यमंत्री को 22 सितंबर को लिखे पत्र में एक राजनीतिक दल पर आरोप लगते हुए कहा है कि इसके करीबी रियल एस्टेट डेवलपर्स का एक वर्ग मराठी लोगों को शहर से बाहर निकाल रहा है। पत्र में नितेश राणे ने कहा है, "नगर पालिका चुनाव



कभी भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। एक बार फिर 'आदित्य सेना' ने आरोप लगाया है कि मुंबई को महाराष्ट्र से काट दिया जाएगा और मराठी लोगों को शहर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो रियल एस्टेट डेवलपर उनके करीब हैं, वह मराठी मुंबईकर को भगाने के लिए दबाव डाल रहा है।

पत्र में आगे लिखा है कि एसआरए में किरायेदार और झुग्गी-झोपड़ी के निवासी पुनर्विकास नियंत्रण नियमों

के तहत निजी डेवलपर्स को प्रोजेक्ट दिया जाता है। हालांकि, कई पुनर्विकास परियोजनाओं में, डेवलपर्स एक से डेढ़ साल के वैकल्पिक स्थान या किराए का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं। लेकिन कई आवास परियोजनाओं में कई डेवलपर्स ने किराया देना भी बंद कर दिया है।

किस पर लगाया है मराठा को परेशान करने का आरोप विकासकों से परेशान लोगों के

लिए नितेश ने कहा कि वे शहर में अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने लिखा है, "एक तरफ कोविड ने मराठी लोगों की आजीविका पर बुरा असर किया है और दूसरी तरफ, मुंबई में एक मराठी व्यक्ति को अपने जीवन के छह घंटे वसई विहार की यात्रा में खर्च करना पड़ रहा है।" नितेश ने यह भी आरोप लगाया है कि विकासकों ने घर को ब्लॉक कर दिया है और किराए का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। कहीं-कहीं घर बनकर तैयार होने के बाद भी न तो भवन का अधिग्रहण किया जाता है और न ही उचित किराया मिलता है। इसी वजह से मराठी परिवारों को अनिवार्य रूप से अपने असली घर को विकासकों या एजेंट को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है।

महाराष्ट्र में ये सरकारी स्कूल होंगे बंद!



मुंबई : महाराष्ट्र में इन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा सकता है, जहां छात्रों की संख्या 20 से कम है। इन छात्रों को पास के स्कूलों में समायोजित करने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्य के शिक्षा आयुक्त, शिक्षा निदेशक को अहम निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य में शून्य से 20 छात्रों वाले स्कूलों की संख्या की समीक्षा करने को कहा गया है। हालांकि इस फैसले का ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किए जाने की संभावना है। साल 2017 में भी राज्य में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन सरकार के दौरान 0 से 20 छात्र वाले 3,314 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था।

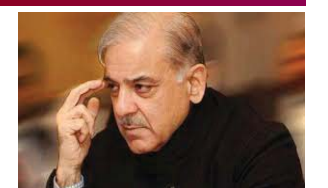
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और अभिभावकों ने किया था विरोध

महाविकास आघाडी सरकार के दौरान भी कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और अभिभावकों ने तब भी सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया था। इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि अब एक बार फिर नई सरकार आने के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी समीक्षा शुरू कर दी है।

जानें क्या है मापदंड ?
शिक्षा विभाग के फैसले के अनुसार कक्षा एक से पांच तक के लिए स्कूल एक किलोमीटर और छठी से आठवीं कक्षा के लिए तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या कम संख्या वाले छात्रों वाले स्कूल बंद होंगे या फिर इस फैसले का विरोध होगा।

दुनिया के सामने फिर गिड़गिड़ाए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बाढ़ में मिली मदद को बताया अपर्याप्त

पाकिस्तानी में विनाशकारी बाढ़ के बाद दुनिया की ओर से दिए गए मदद और आश्वासनों को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुश नहीं हैं। शरीफ ने बाढ़ की वजह से आई तबाही के लिए दुनिया की प्रतिक्रिया को सराहनी बताया है लेकिन कहा कि देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान करीब 30 साल बाद एक बार फिर विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है। स्थिति का अंदाजा इसे से लगाया जा सकता है कि देश का एक तिहाई हिस्सा पानी में डूब गया था।



है वह काबिले तारीफ है लेकिन यह हमारी जरूरतों को पूरा करने से कोसों दूर है। हम इसे अकेले नहीं कर सकते हैं।

बाढ़ की वजह से 30 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान खुद राहत और पुनर्वास कार्य के लिए धन मुहैया नहीं करा सकता है। बाढ़ से करीब करीब 30 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया राहत, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अरबों डॉलर का मदद नहीं करती है, तब तक चीजें वापस सामान्य नहीं होंगी। मुझे अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है और लाखों लोगों को उनके घरों में वापस ले जाना है। शरीफ ने आगे कहा, जब तक हमें पर्याप्त राहत नहीं मिलती, दुनिया हमसे अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद कैसे कर सकती है। यह असंभव जैसा है।



मृत महिला के नाम प्लान पास कराकर बना ली बिल्डिंग!

बिल्डर को नोटिस जारी...!

मुंबई : उल्हासनगर महानगरपालिका के पूर्व आयुक्त रामनाथ सोनावने कहते थे कि उल्हासनगर में कुछ भी हो सकता है। इसी तरह का एक नजारा उल्हासनगर महापालिका में देखने को मिला है, एक चीटर बिल्डर ने मरी हुई महिला के नाम से प्लान पास कराकर बिल्डिंग बना ली है। इस मामले का पदाफांश एक व्यापारी अर्जुन रामरख्यानी ने किया।

इसके बाद उल्हासनगर महानगरपालिका ने बिल्डर को नोटिस जारी की है। नोटिस में लिखा है कि बिल्डर ने लक्ष्मीबाई किशनचंद हरयाणी नामक मृत



महिला के नाम प्लान पास कराकर अब वहां बिल्डिंग भी बना ली। महानगरपालिका ने बिल्डर को नोटिस में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वह पांच दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने में विफल रहा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता-१८६० और महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम-

१९६६ के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त मामले में व्यापारी अर्जुन ने सबूत भी दिया था कि जिन लक्ष्मीबाई हरयाणी के नाम पर बिल्डिंग का प्लान पास हुआ है, उनकी १५ जून २००० को मौत हो गई है और बिल्डिंग का प्लान पास हुआ ५ अगस्त २०१३ को। बिल्डर ने इस बाबत समस्त हस्ताक्षर फर्जी किए और सारे दस्तावेज भी फर्जी जमा किए। महानगरपालिका ने जांच में पाया कि व्यापारी अर्जुन की शिकायत सही है। उसके बाद अब महानगरपालिका ने बिल्डर को नोटिस जारी की है। नोटिस में सीसी को भी रद्द किए जाने का जिक्र है।

उद्धव पर बरसे फडणवीस...

मोदी के नाम पर वोट मांगे, NCP और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तब चुनाव याद नहीं आया?

मुंबई: बीजेपी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक से उद्धव को जवाब दिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव पूरी तरह से हताश और निराश हैं। उन्होंने ठाकरे से पूछा कि क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद उनके विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया था? गठबंधन तोड़ने के बाद नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए था। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे, फिर हमारा साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। किसने किसके पीठ में छुरा घोंपा, फिर चुनाव याद नहीं आया? बुधवार को गोरगांव में गट प्रमुखों को संबोधित करते हुए उद्धव ने केंद्रीय



गृह मंत्री अमित शाह, फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य नेताओं पर हमला बोला। शिंदे सरकार को अवैध बताते हुए इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव कराने की मांग की।

उद्धव ने रैली में कहा था, 'फडणवीस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह बीएमसी का चुनाव अपना आखिरी चुनाव समझ कर लड़ें। मैं आपसे कहता हूँ कि आप

यह अपना पहला चुनाव समझ कर लड़ें, जहां खोने को कुछ नहीं है। इस तरह से बीजेपी को धूल चटाए कि यह फडणवीस का आखिरी चुनाव बने।' इस पर फडणवीस ने जवाब दिया, 'आपने 2019 में ही मुझे खत्म करने की कोशिश की। तीनों मिलकर पिछले ढाई साल में मुझे खत्म करने की कोशिश करते रहे, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। आगे भी आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे।'

हाईकोर्ट ने दी उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत...

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को अनुमति दे। कोर्ट के इस फैसले को शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे द्वारा शिवाजी पार्क में दशहरा



रैली करने की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले बीएमसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के एक आदेश का हवाला दिया था, जिसमें लिखा है कि

न्यायालयों को कानून और व्यवस्था के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसे प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। फैसला सुनाते समय, अदालत ने कहा कि बीएमसी ने

उसी दिन पुलिस रिपोर्ट मांगी जिस दिन ठाकरे गुट ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत ने यह भी कहा कि शिवाजी पार्क में दोनों गुट को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं देने का बीएमसी का फैसला कहीं से भी उचित नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान शिवसेना (ठाकरे गुट) की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में एडवोकेट एसपी चिन्नाय ने कहा, 'शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करता आया है। सिर्फ कोरोना काल में दशहरा मेला का आयोजन नहीं किया गया था। अब कोविड के बाद सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं। ऐसे में इस साल 2022 में शिवसेना की ओर दशहरा मेला आयोजित करने के लिए इजाजत दी जाए। वहीं, बहस के दौरान शिंदे गुट ने कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता हैं। ठाकरे गुट का दावा भ्रामक व गलत तथ्यों पर आधारित है। वहीं, ठाकरे गुट ने परंपरागत रैली शिवाजी पार्क में ही करने की इजाजत देने की मांग की है। शिंदे गुट के वकील मिलिंद साल्वे ने कहा, 'शिवाजीपार्क एक खेलने का मैदान है और साइलेंट जॉन में आता है। साल 2016 का GR है, जिसमें कहा गया है कि दशहरा मेला के लिए शिवाजी पार्क में इजाजत है, लेकिन उसी GR में यह भी कहा गया है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी तो वहां कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता है।'

गिरीश महाजन ने कसा उद्धव ठाकरे पर तंज!

पिंपरी: अब तक 40 विधायक और 12 सांसद शिवसेना छोड़ चुके हैं। बाकी शिवसेना भी उनके हाथ से फिसल रही है। इसलिए उद्धव ठाकरे सिर्फ अपना वजूद दिखाने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों के मुताबिक शिवसेना के पार्टी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का दल आखिरी पायदान पर है। यह बताकर राज्य के ग्राम विकास और पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन ने पिंपरी-चिंचवड में पत्रकारों से की गई बातचीत में ठाकरे को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी। भारत सरकार के पंचायत राज विभाग के माध्यम से पुणे जिला परिषद की ओर से चिंचवड के प्रो. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह में स्वच्छ हरित गांव और पानी समृद्ध गांव विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राज्य के ग्राम विकास एवं पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन इस कार्यशाला में भाग लेने वाले सरपंचों या प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करने पहुंचे थे। महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगाया ये आरोप यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार की निष्क्रियता के कारण वेदांत परियोजना को छोड़ दिया गया था, जिनकी रुचि केवल वाइनरी और शराब पर टैक्स को कम करने में थी। उन्होंने यह आलोचना



भी की है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और शरद पवार को वेदांत परियोजना को लेकर बैठक करने का समय नहीं मिला। मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि हमारे समय में वेदांत यहां से शिफ्ट नहीं हुआ है। 5 जनवरी को सरकार को पत्र दिया गया था, जिस पर छह महीने तक कुछ नहीं किया। कोई बैठक नहीं हुई। इसलिए महाविकास आघाड़ी को आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इसकी आलोचना की बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यह परियोजना इसलिए महाराष्ट्र से चली गई है क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने छह महीने तक कोई जवाब नहीं दिया।

लोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में दिख रहे गिरीश महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते उद्धव ठाकरे ने घर नहीं छोड़ा। मंत्रालय की सिद्धियां नहीं चढ़े। अपने विधायकों, सांसदों तक से बातचीत नहीं की। इसलिए उनमें उदासीनता थी। केवल भड़काऊ भाषण दिए गए।

एसी लोकल : अधिकांश बिना टिकट कर रहे हैं सफर



मुंबई : मुंबई के उपनगरीय रेल मार्ग पर एसी लोकल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेल यात्रियों ने इसका स्वागत भी किया है, परंतु एसी लोकल का किराया आम जनता की पहुंच से दूर है। सुबह और शाम के समय भीड़ के दौरान एसी लोकल का परिचालन किया जाना रेल यात्रियों के लिए मुसीबत है। फिर क्या साधारण लोकल के यात्री भी मौका देखकर चौका मारने से नहीं चूक रहे हैं। कई यात्री बिना टिकट एसी लोकल में सफर कर रहे हैं, जिसकी

वजह से डिब्बे में रेलमपेल की स्थिति बन रही है। ऐसे में आरपीएफ यात्रियों को कोच के भीतर ठेलने के लिए हृदय धक्कावाली नीति अपना रही है।

बता दें कि मुंबई के उपनगरीय एसी लोकल ट्रेन का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो हाल फिलहाल का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एसी लोकल स्टेशन पर पहुंचती है और यात्रियों की भीड़ स्टेशन पर इतनी है कि जिस यात्री को जैसे भी चांस मिल रहा है वो एसी लोकल में

मौका पाकर चढ़ रहा है। ऐसे में एसी लोकल में स्थिति ये हो गई है कि दरवाजे के पास अधिक यात्री होने के कारण एसी लोकल का दरवाजा ही बंद नहीं हो रहा था। जब स्थिति काबू से बाहर हो गई तब स्टेशन पर कार्यरत आरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाला और विदेशों में जिस तरह से यात्रियों को अंदर ठेलने के लिए पुश रखे जाते हैं, ठीक उसी तरह इंडियन स्टाइल में हृदय धक्कावाली तरकीब उन्हें अपनाती पड़ी। काफी मशक्कत कर कुछ यात्रियों को एसी लोकल से उतारने के बाद आरपीएफ को ट्रेन को गंतव्य स्थान की ओर रवाना करने में उन्हें कामयाबी मिली। वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम रेलवे का बताया जा रहा है।



आरईसी को मिला महारत कंपनी का दर्जा

►► पावर सेक्टर की एनबीएफसी आरईसी बनी महारत ►► यह स्टेटस पाने वाली देश की 12वीं सरकारी कंपनी

कंपनी को वित्तीय फैसले लेने में मिलेंगे ज्यादा अधिकार

नई दिल्ली, एजेसी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरईसी को 'महारत' सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिल गया है। यह दर्जा मिलने से कंपनी को ज्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी। आरईसी महारत का खिताब पाने वाली 12वीं कंपनी है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले लोक उपक्रम विभाग ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किया। आरईसी का गठन 1969 में हुआ था। यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो देशभर में पावर सेक्टर के फाइनेंस और डेवलपमेंट पर केन्द्रित है।



पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।

कैसे मिलता है यह दर्जा

इसके अलावा देश में 13 नवरत्न और 74 मिनीरत्न सेंट्रल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर

एंटरप्राइज शामिल हैं। महारत का दर्जा ऐसी कंपनियों को मिलता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो और जिसका सालाना टर्नओवर पिछले तीन साल में 25,000 करोड़ से अधिक हो। साथ ही पिछले तीन साल में इसकी औसत नेटवर्थ 15000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए और औसत नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।

महारत का दर्जा मिलने के बाद आरईसी अब 5000 करोड़ रुपये या अपनी नेटवर्थ का 15 फीसदी तक किसी सिंगल प्रोजेक्ट में निवेश कर सकती है। कंपनी को महारत का दर्जा ऐसे समय मिला है जब सरकार उसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इससे कंपनी देश में ग्लोबल क्लाइमेंट फंडिंग और नेट जीरो इनवेस्टमेंट पर फोकस कर सकती है। अभी यह कंपनी राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्यों की बिजली कंपनियों, इंडिपेंडेंट पावर प्रॉड्यूसर्स, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को वित्तीय सहायता देती है।

बैंकों के फंडे कर्ज में बढ़ी कमी आने की उम्मीद, लेकिन छोटे उद्योगों के मामले में चिंता मुंबई, एजेसी। बैंकों में सकल गैर-निष्पादित आस्तियां यानी फंडा कर्ज चालू वित्त वर्ष में 0.90 प्रतिशत घटकर पांच प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है। इसका कारण बड़ी कंपनियों को दिये गये कर्ज के मामलों में सुधार है। किसिल रेटिंग्स ने बुधवार को रिपोर्ट में यह कहा। इतना ही नहीं वित्त वर्ष 2023-24 में इसमें और कमी आएगी और इसके एक दशक के निचले स्तर चार प्रतिशत पर आने का अनुमान है। किसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि फंडे कर्ज को लेकर सभी चीजें अच्छी नहीं हैं। बैंकों के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) को दिये गये कर्ज को लेकर चिंता है। एमएसएमई कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) मार्च, 2024 तक बढ़कर 10-11 प्रतिशत हो सकता है जो 31 मार्च, 2022 को 9.3 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार, 'पिछले वित्त वर्ष में राहत उपायों से संपत्ति की गुणवत्ता के मामले में स्थिति कुछ ठीक रही।

भारतीय स्टेट बैंक ने बॉन्ड के जरिये 4,000 करोड़ रुपये जुटाए



नई दिल्ली, एजेसी। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने 7.57 प्रतिशत की कूपन दर पर बॉन्ड जारी करके 4,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह राशि बासेल-3 मानकों के अनुरूप टियर-2 बॉन्ड जारी करके जुटाई गई है। एसबीआई ने कहा कि बॉन्डनिर्गम में निवेशकों की जोरदार प्रतिक्रिया देखी गई। इसमें 9,647 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं, जो 2,000 करोड़ रुपये के मूल निर्गम आकार के मुकाबले लगभग पांच गुना है। एसबीआई ने एक विज्ञापन में कहा, 'यह देश के सबसे बड़े बैंक में निवेशकों के भरोसे का प्रतीक है।' बैंक ने निवेशकों की प्रतिक्रिया के आधार पर 7.57 प्रतिशत की कूपन दर पर 4,000 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया।

उद्योगपति गौतम अडाणी ने उद्भव ठाकरे से मुलाकात की

मुंबई, एजेसी। उद्योगपति गौतम अडाणी ने बुधवार को यहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे से मुलाकात की। एक अधिकारी ने कहा, 'बैठक आज हुई।' अधिकारी ने हालांकि यह नहीं बताया कि अडाणी समूह के चेयरमैन और शिवसेना प्रमुख के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे द्वारा उनके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने और जून में पार्टी के 39 विधायकों को तोड़ लेने के बाद ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था।

घट जाएंगी कीमतें, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मिली कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, एजेसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की बिना रुकावट आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के उद्देश्य से पिछले सप्ताह शनिवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का अनावरण किया था। उन्होंने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 फीसदी से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 फीसदी से नीचे लाना चाहिए।

साल 2030 तक भारत को टॉप-25 देशों में पहुंचाना है लक्ष्य

इस नीति का मकसद वर्ष 2030 तक वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कटौती करना है। साथ ही लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार लाना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि हमारा लक्ष्य साल 2030 तक भारत को टॉप-25 देशों की सूची में पहुंचाना है।

सचिवों का समूह करेगा निगरानी

इस नीति की निगरानी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गठित सचिवों का अधिकार



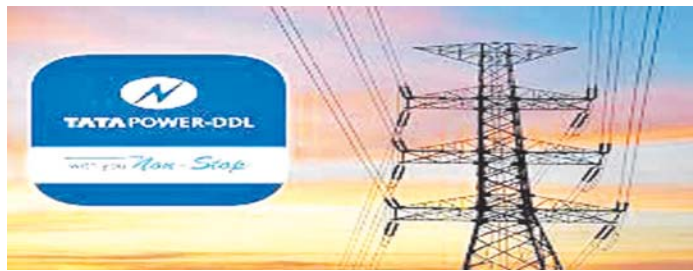
प्राप्त समूह करेगा। प्रक्रियाओं से जुड़े मानदंडों की निगरानी तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डिजिटल और नियामकीय सुधार के लिये यह समूह 'सेवा सुधार समूह' का गठन करेगा।

14 राज्यों ने बनाई अपनी लॉजिस्टिक्स नीतियां

इस नीति के तहत गोदामों के संबंध में उचित विकास का रास्ता खोलने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें अधिकतम स्थान की योजना,

मानकों को प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला का डिजिटलीकरण व स्वचालन तथा बेहतर निगरानी प्रणाली शामिल है। आधिकारिक बयान के अनुसार, 14 राज्यों ने अपनी-अपनी लॉजिस्टिक्स नीतियां बना ली हैं। जबकि, 13 राज्यों में इसका मसौदा तैयार हो रहा है। जुझार लॉजिस्टिक्स के प्रबंध निदेशक अर्शदीप सिंह मुंडी ने नीति को लेकर कहा कि कुशल उपायों के एकीकरण के माध्यम से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

टाटा पावर डीडीएल बिजली चोरी मामलों के निपटान के लिये करेगी लोक अदालत का आयोजन



नई दिल्ली, एजेसी। बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. (टाटा पावर डीडीएल) अपने उपभोक्ताओं के लिये बिजली चोरी और 'कनेक्शन' काटे जाने के मामलों के त्वरित निपटान के लिये लोक अदालत आयोजित करेगी।

उत्तर एवं उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की करीब 70 लाख आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा, 'टाटा पावर डीडीएल दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से 25 सितंबर, 2022 को विशेष लोक अदालत आयोजित करेगी।' बयान के अनुसार, इस विशेष लोक अदालत का आयोजन कंपनी के दिल्ली में रोहिणी स्थित ईएसी ऑफिस में किया जाएगा। इस लोक अदालत में ग्राहकों के बिजली चोरी, मीटर में गड़बड़ी और 'कनेक्शन' काटे जाने के मामलों का तत्काल निपटान किया जाएगा। इस लोक अदालत में ऐसे मामलों पर विचार किया जाएगा जो किसी भी अदालत में लंबित हैं या जिन्हें अभी तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है।

एनसीएलटी ने अजानारा के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, एजेसी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने रियल एस्टेट कंपनी अजानारा लि. के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है और इसके लिये अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। दिल्ली स्थित दो सदस्यीय पीठ ने अजानारा एम्ब्रोसिया के 113 आवंटियों की तरफ से दायरा ऋण शोधन याचिका को स्वीकार कर लिया। बिल्डर-खरीदार समझौते के तहत बुकिंग के तीन साल के भीतर कंपनी घर देने के लिये बाध्य थी, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही।

एनसीएलटी ने कहा, 'कर्ज में फंसी कंपनी ने समझौते के तहत संबंधित घर खरीदारों को मकान देने में चूक की।' पीठ ने कहा कि अजानारा के खिलाफ ऋण शोधन याचिका स्वीकार करने के लिये यह 'उपयुक्त मामला' है। न्यायाधिकरण ने कंपनी पर संपत्ति के हस्तांतरण या निपटान पर भी प्रतिबंध लगाया है। मामला नोएडा के सेक्टर-118 स्थित परियोजना 'अजानारा एम्ब्रोसिया' से जुड़ा है। रियल एस्टेट कंपनी वहां रूफ हाउसिंग सोसायटी का निर्माण कर रही थी। अजानारा एम्ब्रोसिया आवासीय सोसायटी थी। नियम और शर्तों के अनुसार तीन साल की अवधि के भीतर घर खरीदारों को मकान देना था।

कंपनी ने 113 फ्लैट मालिकों से 50.47 करोड़ रुपये लिये लेकिन मकान सौंपने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में वह विफल रही।

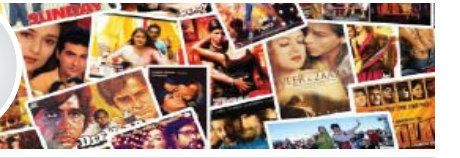
उसके बाद खरीदारों ने एनसीएलटी में याचिका दायर की। कंपनी ने याचिका स्वीकार किये जाने का विरोध किया जिसे एनसीएलटी ने खारिज कर दिया।

इस बार त्योहारों में 300 रुपये कम में घर लाएं एलपीजी सिलेंडर



नई दिल्ली, एजेसी। 26 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही त्योहारों की झड़ी लग जाएगी। दशहरा, दीवाली, भैया दूज, छठ पूजा जैसे तमाम त्योहारों की खुशियां घर-आंगन में बिखरेगी। ऐसे में खूब पकवान बनेंगे। पकवान बनेंगे तो एलपीजी भरा सिलेंडर भी खाली होगा और इसमें अंदाजा नहीं होगा कि कब खत्म होने वाला है। तो चलिए आपको यह टेंशन हम दूर कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके घरेलू सिलेंडर में कितना गैस बचा है, तो आपको ऐसा सिलेंडर लाना पड़ेगा, जिसमें गैस दिखाती हो और ऐसा सिलेंडर मार्केट में बहुत दिन पहले ही आ चुका है। यह देखने में आकर्षक तो है ही, साथ में 14.2 किलो वाले सिलेंडर से 300 रुपये कम में मिलता है। साथ ही गैस भी दिखाती रहती है। बता दें इस सिलेंडर में केवल 10 किलो ही गैस रहेगी।

बाजार में आने वाला कंपोजिट सिलेंडर लोहे के सिलेंडर के मुकाबले 7 किलो हल्का है। इसमें थ्री-लेयर होंगे। बता दें अभी इस्तेमाल होने वाला खाली सिलेंडर 17 किलो का होता है और गैस भरने पर यह 31 किलो से थोड़ा अधिक पड़ता है। अब 10 किलो के कंपोजिट सिलेंडर में 10 किलो ही गैस होगी।



हार्डी संधू और परिणीति चोपड़ा

की फिल्म 'कोड नेम तिरंगा' का टीजर रिलीज

अभिनेता हार्डी संधू और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की आने वाली फिल्म कोड नेम तिरंगा का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टी-सीरीज, रिलायंस एंटरटेनमेंट, फिल्म हैंगर और फिल्म निर्माता रिभु दासगुप्ता की आने वाली फिल्म कोड नेम: तिरंगा में परिणीति चोपड़ा और हार्डी संधू की मुख्य भूमिका हैं। इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस टीजर में हार्डी और परिणीति बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म में परिणीति चोपड़ा एक रॉ एजेंट की भूमिका



निभा रही हैं, जिसमें वह कई देशों में मिशन पर जाती दिखेंगी। इस फिल्म में परिणीति और हार्डी के अलावा शरद केलकर, दिव्येंदु भट्टाचार्य, रजित कपूर, शिशिर शर्मा, सब्यसाची चक्रवर्ती और दीश मारीवाला जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभाएंगे। कोड नेम: तिरंगा गुलशन कुमार, टी-सीरीज फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है और भूषण कुमार, रिलायंस एंटरटेनमेंट, फिल्म हैंगर, विवेक बी अग्रवाल द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज होगी।

'डबल एक्सएल'

उन सभी के लिए जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं: **हुमा कुरैशी**

अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने खुलासा किया कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ उनकी आने वाली फिल्म डबल एक्सएल की कहानी उनके जीवन में एक मजेदार बातचीत के रूप में शुरू हुई क्योंकि सभी कलाकार लॉकडाउन के बाद वजन को लेकर परेशान थे। हुमा ने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा किया कि यह विचार कैसे आया। उन्होंने लिखा, मेरे सबसे करीबी दोस्तों और परिवार के साथ एक मजेदार बातचीत के रूप में शुरू हुआ सोनाक्षी, जहीर, साकिब और मुदस्सर, सचमुच मेरे लिविंग रूम में, और अब यह इस फिल्म का परिणाम है। सभी कलाकार लॉकडाउन के बाद वजन के बारे में विलाप कर रहे थे जो हमने हासिल किया था और मुदस्सर ने इसके इर्द-गिर्द एक कहानी

गढ़ी थी। इस कहानी को बाद के महीनों में अधिक से अधिक दोस्तों के साथ-साथ साझेदार भी मिले क्योंकि हमने इस यात्रा में साथ दिया। यह एक फिल्म है जिसे बहुत प्यार से लिखा और बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने डबल एक्सएल के सपने में शामिल होने और इसे साकार करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, यह फिल्म उन सभी के लिए है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। फिल्म एक सोशल कॉमेडी ड्रामा है, जिसके लिए दोनों अभिनेत्रियों ने बड़े पैमाने पर अपने लुक के लिए मेहनत की है और फिल्म में अपनी भूमिकाओं के लिए अतिरिक्त वजन भी बढ़ाया है, फिल्म को भारत और यूके में बड़े पैमाने पर शूट किया गया है।

चिरंजीवी और सलमान के गाने

'थार मार' ने **यूट्यूब** पर किया ट्रेंड

मेगास्टार चिरंजीवी और सलमान खान स्टार फिल्म गॉडफादर का पहला गाना थार मार, जिसका निर्देशन मोहन राजा



ने किया है, अब तक यूट्यूब पर 11 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। मास डांस नंबर, जिसमें चिरंजीवी और सलमान खान ने अपने अनोखे अंदाज और क्लासी स्टेप्स से डांस फ्लोर पर धमाल मचा दिया है, अभी भी यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। सलमान खान और चिरंजीवी के स्टारडम को गौरवान्वित करने वाले इस गाने को एस थमन ने कंपोज किया है और प्रभु देवा ने कोरियोग्राफ किया है। श्रेया घोषाल ने आकर्षक फुट-टैपिंग नंबर गाया है जिसमें अनंत श्रीराम के बोल हैं। गॉडफादर, अब तक के सबसे बड़े एक्शन एंटरटेनर में से एक है, जिसमें नयनतारा, सत्य देव, सुनील और समुथिरकानी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। आरबी चौधरी और एनबी प्रसाद कोनिडेला प्रोडक्शंस और सुपर गुड फिल्म्स के बैनर तले भव्य अंदाज में फिल्म का निर्माण कर रहे हैं और कोनिडेला सुरेखा इसे पेश कर रही हैं।

दिनेश कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की 3 गलितयां

रोहित शर्मा ने मैच में ही पकड़ ली भारतीय विकेटकीपर की गर्दन

मोहाली (एजेंसी)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की सीरीज का पहला टी20 20 सितंबर 2022 की रात मोहाली में खेला गया। भारतीय टीम ने 4 विकेट से यह मुकाबला गंवा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 209 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन खराब गेंदबाजी के चलते वह इसका बचाव नहीं कर पाया। दिनेश कार्तिक के लिए भी यह मैच यादगार नहीं रहा। बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग दोनों मामले में फेल रहे।

सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए दिनेश कार्तिक 5 गेंद में 6 रन बनाकर नाथन एलिस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान विकेटकीपिंग करते हुए उनसे तीन गलितयां हुईं। शायद यही वजह रही है रोहित शर्मा ने एक बार तो मैच के दौरान ही उनका चेहरा पकड़ लिया। हालांकि, उन्होंने ऐसा मजाक में ही किया था। शायद वह कहना चाह रहे हों कि कुछ तो



बता मेरे भाई। दिनेश कार्तिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में विकेट के पीछे कॉन्फिडेंस में नहीं दिखे। हुआ यह कि उमेश यादव की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से एज लगकर गेंद दिनेश कार्तिक के दस्ताने में समा गई। भारतीय विकेटकीपर ने आउट की अपील तो की, लेकिन वह रिव्यू लेने का आत्मविश्वास नहीं दिखा पाए। कार्तिक शायद रोहित से कह रहे थे कि वह आवाज को लेकर निश्चित नहीं हैं।

वहीं, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पूरा विश्वास था कि गेंद ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले का बाहरी किनारा छूते हुए विकेटकीपर के पास गई है। ऑन-फील्ड अंपायर ने ग्लेन मैक्सवेल को नॉट आउट करार दिया। इसके बाद रोहित ने रिव्यू लिया। तीसरे अंपायर ने पुष्टि की कि गेंद वास्तव में मैक्सवेल के बल्ले से छूकर गई थी। इसकी पुष्टि अल्ट्रा-एज के जरिए हुई।



शरीर के लिए आवश्यक है फाइबर, कमी से होते हैं रोग

फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी खाद्य सामग्री में हरी सब्जियाँ, टमाटर, भिंडी, पालक, खीरा, हरी मिर्च, दही, साबुत अनाज और ब्रोकली को अवश्य शामिल करें। अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में आप सुबह या शाम को हल्के नाश्ते के रूप में फलों का सेवन कर सकते हैं। फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए आप संतरा, अनानास, केला, पपीता, कीवी, चीकू, अनार आदि को ले सकते हैं। इन फलों के सेवन से न सिर्फ फाइबर की कमी पूरी होती है अपितु इन फलों का सेवन आपको तंदरुत और तर्रोताजा भी रखता है।

ब्लड शुगर लेवल

फाइबर की कमी से ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव आने लगते हैं। मधुमेह (डायबिटीज) के रोगियों में फाइबर की कमी के कारण ही वजन बढ़ने की समस्या दिखाई देती है। मधुमेह से पीड़ितों को फाइबर की पर्याप्त मात्रा अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए इससे ब्लड शुगर सही रहता है। जो लोग डायबिटीक नहीं होते हैं उनका वजन भी कई बार फाइबर की कमी की वजह से बढ़ने लगता है। फाइबर युक्त भोजन करने से वजन संतुलित रहता है।

पाचन तंत्र कमजोर या कब्ज की शिकायत रहना

फाइबर की कमी के चलते हमें कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है। कब्ज अर्थात् पेट का सही तरीके से साफ न होने से हमारे में चिड़चिड़ापन, खीझ और घबराहट के साथ असीडिटी की समस्या होने लगती है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का फाइबर की कमी के कारण पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए अपनी खाद्य सामग्रियों में फाइबर युक्त सब्जियों को जरूर शामिल करें। इससे आपको इन दोनों समस्याओं से निजात मिल सकेगी।

जी मिचलाना

आप दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जी मिचला रहा है और उल्टी होने वाली है, तो यह शरीर में फाइबर की कमी का स्पष्ट संकेत है। इस समस्या के बचाव के लिए आपको अपने भोजन में हाई प्रोटीन फूड कैलोरी का सेवन करना चाहिए।

जिस तरह से शरीर के पोषक तत्वों के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन की आवश्यकता होती है उसी तरह से हमारे शरीर के लिए फाइबर की भी बहुत महत्ता है। यह शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों में से है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में फाइबर की कमी होने से कई प्रकार की समस्याएँ होने लगती हैं।



हार्ट अटैक के इन लक्षणों को ना करें अनदेखा

हार्ट अटैक या दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय की मांसपेशियों के एक हिस्से को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति को जल्द से जल्द चिकित्सीय मदद की जरूरत होती है। रक्त प्रवाह को बहाल करने के लिए उपचार के बिना जितना अधिक समय बीतता है, हृदय की मांसपेशियों को उतना ही अधिक नुकसान होता है। कभी-कभी तो समय पर इलाज ना मिलने के कारण व्यक्ति की जान तक चली जाती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज (सीएडी) दिल के दौरे का मुख्य कारण है। आमतौर पर, जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव नजर आते हैं। हालांकि, अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर उन्हें गंभीर परिणाम उठाने पड़ते हैं।

सीने में दर्द या बेचैनी

यह एक सामान्य लक्षण है, जो अधिकतर

लोगों को दिल का दौरा पड़ने पर नजर आता है। इस स्थिति में व्यक्ति को छाती के केंद्र या बाईं ओर असुविधा होती है जो कुछ मिनटों से अधिक समय तक रहती है या जो चली जाती है और वापस आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को बेचैनी के साथ-साथ असहजता, दबाव या दर्द की तरह महसूस हो सकता है।

कमजोरी महसूस करना

जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो इसका अर्थ है कि उसका हृदय सही तरह से काम नहीं कर रहा है। इस स्थिति में व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस कर सकता है या फिर उसे हल्का सिर में दर्द या बेहोशी का भी अहसास हो सकता है। कुछ लोगों को टंडे पसीने में भी टूट सकते हैं।

असहज महसूस करना

कई बार व्यक्ति को हार्ट अटैक होने पर जबड़े, गर्दन या पीठ में दर्द या बेचैनी हो

जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो इसका अर्थ है कि उसका हृदय सही तरह से काम नहीं कर रहा है। इस स्थिति में व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस कर सकता है या फिर उसे हल्का सिर में दर्द या बेहोशी का भी अहसास हो सकता है।

सकती है। कुछ लोगों को इस दौरान एक या दोनों बाहों या कंधों में दर्द या बेचैनी का अनुभव भी हो सकता है।

सांस लेने में कठिनाई

जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसे अक्सर सीने में तकलीफ भी होती है। हालांकि, सीने में तकलीफ से पहले सांस की तकलीफ भी हो सकती है। जिससे व्यक्ति को दर्द के साथ-साथ सांस लेने में कठिनाई का अहसास हो सकता है। दिल के दौरे के अन्य लक्षणों में असामान्य या अस्पष्टीकृत थकान और मतली या उल्टी शामिल हो सकती है। महिलाओं में इन लक्षणों की संभावना अधिक होती है।

पितृ पक्ष में इन पेड़ों की पूजा करने से प्राप्त होगा पितरों का आशीर्वाद

पितृ पक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से हो चुकी है। 15 दिनों के पितृ पक्ष में पितरों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान पिंडदान और दान-कर्म करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ दोष दूर करने के लिए कुछ पेड़ों की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानें कौन से ये पेड़।

पितृ दोष से मुक्ति पाने और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप इस दौरान कुछ पेड़ों की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन पेड़ों की पूजा करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसमें बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और बेल का पेड़ आदि शामिल है। पितृ पक्ष में इन पेड़ों की पूजा करने का महत्व क्या है यहां जानें।



बरगद का पेड़ - बरगद को वट का वृक्ष भी कहा जाता है। पितृ पक्ष में इस पेड़ की पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ पक्ष में जल में काले तिल मिलाकर बरगद के पेड़ को अर्पित करें। ऐसा माना जाता कि इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है।

पीपल का पेड़ - पितृ पक्ष में पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस अवधि के दौरान नियमित रूप से दोपहर के समय जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ को अर्पित करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पितृ सूक्त का पाठ करें।

बेल का पेड़ - ऐसा माना जाता है कि बेल का पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृ पक्ष में रोजाना सुबह के समय जल में गंगाजल मिलाकर बेल के पौधे को अर्पित करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है।



नवरात्रि में खुलेगा कलवा खाड़ी पर बना तीसरा ब्रिज !

ठाणे : ठाणे और कलवा को जोड़ने वाले निर्माणाधीन तीसरे पुल के एक लेन को नवरात्र उत्सव के दौरान खोला जा सकता है। क्योंकि कलवा पुल पर हो रहे यातायात जाम की समस्या और लोगों को हो रहे परेशानी को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक जितेंद्र अट्टाड ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर इसे जल्द खोलने की मांग की। अट्टाड ने बताया कि पुल के एक लेन के लोकार्पण को मुख्यमंत्री ने सकारात्मक दिखे और उन्होंने संबंधित विभाग को आदेशित किया है।



गौरतलब हो कि कलवा खाड़ी पर ब्रिटिश कालीन ब्रिज की जर्जर अवस्था में होने के बाद महानगरपालिका प्रशासन की तरफ से शुरू तीसरे निर्माणाधीन पुल का कार्य प्रगति पथ पर है। काम की शुरूवात

के सात वर्ष बाद भी कलवा खाड़ी पर निर्माणाधीन तीसरे पुल का काम पूरा नहीं हो पाया है। जिसके चलते ठाणे के लोगों की परेशानी बढ़ी है। इसके चलते कलवा, खरिगाव-बेलापुर मार्ग की तरफ जाने वाले वाहनों को लगातार ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। पुल के एक लेन को दिसंबर 2021 में शुरू किया जाना था लेकिन नहीं शुरू हुआ। उसके बाद मई और जून 2022 की डेडलाइन दी गयी। फिर जुलाई 2022 के अंत तक साकेत परिसर और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास

के दो लेन को शुरू करने की बात कही गयी, लेकिन अभी यह संभव नहीं है। आगे कब शुरू होगा इस बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

तीन वर्ष बजाय लगे सात वर्ष
वाहनों चालकों और कलवा वासियों की समस्याओं को देखते हुए महानगरपालिका प्रशासन ने वर्ष 2014 में कलवा खाड़ी पर ही तीसरे पुल का निर्माण करने की शुरूवात की। इस पुल के निर्माण का कुल लागत 183 करोड़ 66 लाख 61 हजार 353 रूपए है। इसके लिए 12 सितंबर, 2014

को पुल के निर्माण का वर्क ऑर्डर महानगरपालिका प्रशासन की तरफ से पूल बनाने वाली कंपनी को दिया गया था। इस पुल के निर्माण की कुल कालावधि तीन साल थी। अर्थात इस पुल का निर्माण सितंबर 2017 तक हो जाना चाहिए था लेकिन सात वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है।

पुल के निर्माण में देरी का मुख्य कारण

पुल के निर्माण में देरी होने के संदर्भ में महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग का कहना है कि पूल का कुछ हिस्सा सीआरजेड के अंतर्गत आता है जिसकी मंजूरी मिलने में देरी हुई। साथ ही यहाँ पर शास्त्री नगर की कुछ झोपड़िया भी बाधक थी। जिसे हटाने में समय लगा।

मुंबई में बम धमाके की धमकी, सांताक्रूज इलाके में एक शख्स को आया फोन

मुंबई : मुंबई में बम धमाकों की धमकी भरे कॉल किए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि सांताक्रूज इलाके के कई लोगों को फोन कर इस आशय की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारद्वि की धारा 506 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने फोन कॉल करने वाले की लोकेशन का पता लगा लिया है। उसे दबोचने के प्रयास जारी हैं।



एआईएमआईएम के कार्यालय पर हमला
ठाणे शहर के मुंब्रा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) कार्यालय पर कथित तौर पर अज्ञात व्यक्तियों के एक समूह ने हमला किया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस निरीक्षक अशोक कदलाग के मुताबिक यह घटना गुरुवार रात करीब दस बजे की है। हमला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। पुलिस निरीक्षक (एसपी) अशोक कदलाग ने बताया कि करीब दर्जन अज्ञात लोगों के समूह ने मुंब्रा में एआईएमआईएम के कार्यालय पर हमला किया। शिकायत के आधार पर इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने आगे बताया कि हमले के पीछे के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मुंबई की अदालत ने सांसद नवनीत राणा

उनके पिता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट किया जारी...!



मुंबई: शहर की मजिस्ट्रेट अदालत ने जाति प्रमाण पत्र के मामले में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल उनके और उनके पिता के खिलाफ जारी की गई यह दूसरी गैर जमानती वारंट है। राणा जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सांसद, जो हनुमान चालीसा पंक्ति में उलझे हुए थे, ने दावा किया कि वह अनुसूचित जाति से थीं और इसलिए चुनाव के लिए खड़ी हुईं। हालांकि, उसके और उसके पिता के

खिलाफ मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में फर्जी तरीके से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र बनाकर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का मामला दर्ज किया गया था। राणा और उनके पिता हरभजन सिंह राम सिंह कुंडलेस के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। कथित तौर पर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल जून में उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था और नकली जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 2 लाख रुपये का जुमाना लगाया था। अदालत ने पाया था कि उसने जाली दस्तावेज पेश करके फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाया था और इसे रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने कहा कि मोची जाति से संबंधित होने का उनका दावा अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार को उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के इरादे से किया गया था।

बोरिवली के नेशनल पार्क में फिर शुरू होगी 'वनराणी'



मुंबई : बोरिवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही 'वनराणी' ट्वाय ट्रेन एक बार फिर शुरू की जाएगी। साथ ही अभिनेत्री रवीना टंडन को राज्य की वन्यजीव सदिच्छा दूत नियुक्त किया गया है। यह जानकारी राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने नेशनल पार्क में टॅक्सिडर्मी सेंटर, वन्य जीव अस्पताल एवं कैट ओरिएंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। बोरिवली

नेशनल पार्क में 'वनराणी' ट्वाय ट्रेन चलती थी, जिसका लुप्त केवल बच्चे नहीं अपितु हर वर्ग के लोग उठाते थे, लेकिन बाद में इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया। मुनगंटीवार ने बताया कि देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश की सर्वोत्तम ट्रेन को इस उद्यान में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्यान में बच्चों के साथ ही प्रत्येक व्यक्तियों के लिए ट्रेन आकर्षण का केंद्र होती है। यह ट्रेन परिवार को बांधे रखने और उनके

चहरे पर हंसी लाने का काम भी करती है। रवीना टंडन राज्य सरकार की वन्यजीव सदिच्छादूत वन मंत्री मुनगंटीवार ने टी फॉर टंडन, टायगर और ट्री का जिक्र करते हुए कहा कि अभिनेत्री रवीना टंडन राज्य सरकार की वन्यजीव सदिच्छादूत के रूप में काम करेगी। इससे वन्यजीव संरक्षण और संवर्धन में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि जिस तरह रवीना टंडन को उनके सशक्त अभिनय के लिए जाना जाता है उसी तरह महाराष्ट्र को वाघों और वृक्षारोपण के लिए भी पहचाना जाता है। वन मंत्री रहते हुए हमने राज्य में वाघों की संख्या 190 से 312 करने और 50 करोड़ पेड़ लगाने की परियोजना शुरू किया। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि जिस तरह शहरों के लिए विकास प्ररूप तैयार किया जाता है उसी तरह वन विभाग के माफत वन संरक्षण और संवर्धन के लिए प्ररूप तैयार किया जाएगा।

मुंबई लोकल ट्रेन में महिला वकील से कथित तौर पर छेड़छाड़, मामला दर्ज...



मुंबई : मुंबई लोकल ट्रेन में आज एक महिला वकील से कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। अंधेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और महिला वकील की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। पीड़िता द्वारा उसके प्रति पुलिस अधिकारियों के बुरे व्यवहार के आरोप की जांच के आदेश दिए गए हैं।